न्यायाधीश राजीव नारायण रैना के समक्ष

पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगरमिल्स लिमिटेड—*याचिकाकर्ता*

बनाम

अपर रजिस्ट्रार (डी) सहकारी समितियां पंजाब, सीएच अंदीगढ़ और अन्य- *प्रतिवादी*

2009 की CWPNo.6156

28 फरवरी, 2012

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, जे 961 -एसएस 68,69 - हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 - एस एस 114,115 - सामान्य संवर्ग सेवा नियम, 1981 - नियमित जांच में अपराधी के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए - प्रबंध निदेशक ने सजा के माध्यम से संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोक दी - निदेशक मंडल के समक्ष अपील में, अपीलीय प्राधिकारी ने चीनी मिल को कोई जानबूझकर नुकसान नहीं पाया - परिणामतः वसूली आदेश जीवित नहीं रहा - प्रबंध निदेशक ने पंजाब की धारा 69 के तहत संशोधन याचिका को प्राथमिकता दी सहकारी समिति अधिनियम, 1961 जिसे अनुरक्षणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया था - प्रबंध निदेशक, चीनी फेड द्वारा दायर रिट याचिका - ने माना कि न तो चीनी फेड और न ही इसके प्रबंध निदेशक निदेशक मंडल के निर्णय को चुनौती देने के लिए सक्षम थे - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि न तो शुगरफेड और न ही इसके प्रबंध निदेशक निदेशक मंडल की उप-समिति के निर्णय को चुनौती देने के लिए सक्षम थे, जिसमें अधिनियम की धारा 69 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को आमंत्रित करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब आरसीएस का कोई नामांकित व्यक्ति उपस्थित और निर्णय नहीं ले रहा था।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ता के *लिए विकास सिंगली एडवोकेट।*

ओ.पी. डाबला, डीएजी, पंजाब। प्रतिवादी नंबर 2 के लिए हरित शर्मा, एडवोकेट।

राजीव नारायण रैना, जे।

(एक) तत्काल रिट याचिका और दो अन्य संबंधित रिट याचिकाओं* का निपटारा एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि तीन मामलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं। तथ्यों को सुविधा के लिए 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6156 से लिया गया है।

(दो) तथ्य एक संकीर्ण कम्पास में निहित हैं। प्रतिवादी नंबर 2 - एचएस सारंगल और दो अन्य एसएल कौशल और जसबीर सिंह प्रतिवादियों को संबंधित रिट याचिकाओं में कदाचार के लिए आरोपित किया गया था। याचिकाकर्ता शुगरफेड के साथ उनकी सेवा शर्तें कॉमन कैडर सर्विस रूल्स, 1981 के प्रावधानों द्वारा शासित थीं। वर्ष 2004 में उन्हें अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनके उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आरोप-प्रत्यारोप जारी करके नियमित जांच कार्यवाही शुरू की गई। मोरिंडा सहकारी चीनी मिल, मोरिंडा में कार्य करते हुए उन्हें नियमित जांच का सामना करना पड़ा। श्री केसी मैनी (आईएएस) ने कहा कि जांच अधिकारी थे जिन्होंने जांच की थी। उन्होंने दिनांक 08.10.2003 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। आरोप साबित हुए। उन सभी को सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्तावित दंड जारी किया गया था और साथ ही तीन चूककर्ताओं, आरोपित अधिकारियों से समान अनुपात में नियोक्ता को हुई अच्छी आर्थिक हानि का दंड लगाया गया था। प्रबंध निदेशक, सुगरफेड ने दिनांक 21022005 के आदेश के तहत इसे सेवा से बर्खास्त करने का उपयुक्त मामला नहीं पाया और इसके बजाय तीनों से संचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आदेश दिया कि 6,98,323 रुपये की वसूली तीनों द्वारा समान रूप से साझा की जाए।

(तीन) जुर्माना लगाने के आदेश से व्यथित, दूसरे प्रतिवादी ने 2006 में शुगरफेड के निदेशक मंडल के समक्ष एक वैधानिक अपील को प्राथमिकता दी। तीनों अपीलों पर दिनांक 06.12.2006 के एक सामान्य आदेश (पी-2) द्वारा निर्णय लिया गया था। निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच से अपील सुनने के लिए निदेशक मंडल द्वारा गठित एक उप समिति द्वारा अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशों का पालन नहीं करने का दोषी ठहराया, लेकिन उन्हें चीनी मिल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का दोषी नहीं पाया। परिणाम में, वसूली आदेश बच नहीं पाया।

(चार) अपने निदेशक मंडल के निर्णय से असंतुष्ट चीनी प्रचालक ने रजिस्ट्रार के समक्ष पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 69 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की

सहकारी समितियां, पंजाब। इस संशोधन की सुनवाई अतिरिक्त रजिस्ट्रार (डी) द्वारा की गई जिन्होंने दिनांक 28-08-2008 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। (ङ) ने निर्णय दिया कि धारा 69 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका बीओडी - अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध नहीं है क्योंकि बीओडी-अपीलीय प्राधिकारी रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के अधीनस्थ प्राधिकरण नहीं है। प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल के अधीनस्थ माना गया था और सहकारी समिति के उपनियमों ने उन्हें बीओडी के निर्णयों को चुनौती देने के लिए अधिकृत नहीं किया था और इसलिए, प्रबंध निदेशक अपने वरिष्ठ सांविधिक प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते थे।

(पाँच) याचिका पर नोटिस जारी होने पर प्रतिवादियों ने पेशी कराई है। संयुक्त रजिस्ट्रार (खेती) सहकारी समितियां, पंजाब ने संक्षिप्त हलफनामे के माध्यम से एक जवाब दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आक्षेपित आदेश अर्ध-न्यायिक क्षमता में पारित किया गया है और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 केवल प्रोफार्मा पार्टी है और प्रतिवादी नहीं है। प्रतिवादी - एचएस सरन गल ने संबंधित मामलों में दो अन्य उत्तरदाताओं के लिए भी जवाब दाखिल किया। वर्तमान मामले में विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह उठता है कि क्या संशोधन बनाए रखने योग्य था।

(छः) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विकास सिंह ने याचिका की विचारणीयता के रूप में अपने तर्क को सीमित रखा है और सुनवाई में मामले की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया है।

(सात) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(आठ) श्री हरित शन्ना, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सजा का आदेश निदेशक मंडल द्वारा गठित उप-समिति द्वारा पारित किया गया था जिसमें आरसीएस, पंजाब का कोई नामांकित व्यक्ति नहीं था। '1' उसका अंतिम निर्णय समाज में ही था। धारा 69 के तहत एक संशोधन केवल तभी सक्षम होगा जब धारा 68 के तहत सरकार के पास कोई अपील नहीं है। वर्तमान मामले में सरकार ने *स्वतः संज्ञान* में या किसी पक्ष के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वर्तमान मामले में इन दोनों सामग्रियों का अभाव है। श्री विकास सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **जसबीर सिंह और अन्य** *बनाम* **आयुक्त (अपील) जालंधर डिवीजन और अन्य**

(1) 2011 (3) पीएलआर 545

में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर (1) में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कई मुद्दों को पीटा गया है

(1) 2011 (3) पीएलआर 545

पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 की धारा 69 और धारा में निहित इसके समरूप प्रावधान दोनों की पृष्ठभूमि में। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 115 उनका तर्क है कि दोनों प्रावधानों के तहत एक पीड़ित व्यक्ति लागू हो सकता है कि वह संदर्भ का पक्ष है या नहीं। पुनरीक्षण का यह उपाय केवल उस मामले में वर्जित है जहां आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील पंजाब अधिनियम की धारा 68 के तहत है। दोनों विद्वान वकील पूर्ण पीठ के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं। श्री हरित शर्मा, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने के लिए उसी निर्णय पर भरोसा करेंगे कि संशोधन का एक उपाय क्या समाज द्वारा पारित आदेश के खिलाफ नहीं किया जा सकता है या नहीं। उक्त शक्ति का प्रयोग केवल अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय या आदेश या अधिनियम से उत्पन्न कार्यवाही, या उसके तहत बनाए गए नियमों के खिलाफ किया जा सकता है। श्री शन्ना, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि यहां पार्टियों पर लागू सामान्य कैडर नियम वैधानिक नियमों के समान हैं और समान स्तर पर खड़े हैं और इसलिए वैधानिक पक्ष हैं। पूर्ण पीठ के फैसले का पैरा 35 इस प्रकार है: -

> "35. सेवा नियमों की तीन श्रेणियां हैं जिन्हें सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में, सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के सेवा नियम बना सकती है। नियम सोसायटी और उसके कर्मचारियों के बीच बाध्यकारी हो सकते हैं।
>
> नियमावली की दूसरी श्रेणी वे नियम हैं जो धारा 85(2)(xxxviii) के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो सरकार को किसी सहकारी समिति या समिति के कर्मचारियों की अर्हताओं और सेवा की शर्तों के संबंध में किसी सहकारी समिति या समितियों के वर्ग के लिए सेवा नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं जिनके अधीन सोसायटियों द्वारा व्यक्तियों को नियोजित किया जा सकता है। इस प्रकार बनाए गए ऐसे नियमों में संविधि का बल होता है और इन्हें संविधि के एक भाग के रूप में समाविष्ट किया जाता है, जबकि यह सिद्धांत सोसायटी द्वारा बनाए गए नियमों की पहली श्रेणी पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे नियम केवल समाज के आंतरिक प्रबंधन, व्यवसाय या प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। वे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनी के संगम अंतनयमों की प्रकृति के होते हैं। उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बीच बंधन हो सकता है, लेकिन उनके पास एक क़ानून का बल नहीं है।
>
> लेकिन नियमों की दूसरी श्रेणी सांविधिक नियम हैं और उन्हें संविधि का बल प्राप्त है। इसी तरह, नियमों की तीसरी श्रेणी है जिसे सामान्य संवर्ग नियमों के रूप में जाना जाता है। इन नियमों को

पंजाब अधिनियम की धारा 84-ए के तहत तैयार किया जा सकता था जो यह प्रदान करता है कि एक शीर्ष समिति स्वतः प्रेरणा से और जब रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो समाज की सेवा में या केंद्रीय समितियों की सेवा में सभी के एक सामान्य संवर्ग या कर्मचारी के निर्दिष्ट वर्ग का गठन किया जा सकता है जो शीर्ष सोसायटी के सदस्य हैं या प्राथमिक समितियों के सदस्य हैं जो शीर्ष समाज के सदस्य हैं। उप-धारा (2) आगे, यह प्रदान करता है कि जब उप-धारा (1) के तहत कर्मचारी का एक सामान्य संवर्ग गठित किया जाता है, तो रजिस्ट्रार किसी भी कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद लागू या किसी भी समझौते, निपटान या पुरस्कार ऐसे कर्मचारियों को स्वीकार्य वेतनमान और भत्ते निर्धारित करेगा और शीर्ष समिति रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाएगी। इसलिए, रजिस्ट्रार द्वारा उप-धारा (2) के तहत बनाए गए सामान्य कैडर नियमों का भी वैधानिक रंग है और वैधानिक नियम के समान पायदान पर खड़ा है।

(नौ) पूर्ण पीठ के निष्कर्ष पैरा 54 में दर्ज किए गए हैं और नीचे दिए गए हैं: -

"54. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: -

(१) पंजाब अधिनियम की धारा 69 के तहत राज्य सरकार या रजिस्ट्रार और हरियाणा अधिनियम की धारा 115 के तहत राज्य सरकार एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अपने स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है, चाहे वह संदर्भ का पक्षकार हो या नहीं।

(२) संशोधन का एकमात्र उपाय केवल तभी रोक दिया जाता है जब आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील पंजाब अधिनियम की धारा 68 या हरियाणा अधिनियम की धारा 114 के तहत हो।

(३) पुनरीक्षण का उपाय उन मामलों में वर्जित नहीं है जहां पीड़ित व्यक्ति को वैधानिक सेवा नियमों या सामान्य संवर्ग नियमों के तहत अपील का अधिकार है।एक पीड़ित पक्ष पंजाब अधिनियम की धारा 69 या हरियाणा अधिनियम की धारा 115 के तहत एक संशोधन दायर करके वैधानिक नियमों या सामान्य कैडर नियमों के तहत अपीलीय प्राधिकारी के

रूप में पारित रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दे सकता है क्योंकि इस तरह के आदेश के खिलाफ पंजाब अधिनियम की धारा 68 या हरियाणा अधिनियम की धारा 114 के तहत अपील का कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन यदि अपीलीय आदेश सोसाइटी के अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है न कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा, तो ऐसे आदेश के खिलाफ कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह पुनरीक्षण केवल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से उत्पन्न कार्यवाही के विरुद्ध ही विचारणीय है।

(४) सोसायटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ या तो स्वत: या *अन्यथा संशोधन का उपाय* लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त शक्ति का प्रयोग अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय या आदेश या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों से उत्पन्न कार्यवाही के खिलाफ किया जा सकता है।

(५) संशोधन की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, जहां पंजाब अधिनियम की धारा 69 या हरियाणा अधिनियम की धारा 115 के तहत संशोधन स्वयं इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है कि आक्षेपित आदेश के खिलाफ पंजाब अधिनियम की धारा 68 या हरियाणा अधिनियम की धारा 114 के तहत या किसी अन्य आधार पर अपील प्रदान की गई है। यदि सरकार या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, किसी पीड़ित पक्ष के आवेदन पर या अन्यथा संशोधन की शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसे आदेश में विशेष रूप से कहा जाना चाहिए।

(दस) श्री हरित शर्मा, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील रेखांकित शब्दों पर भरोसा करेंगे।

(ग्यारह) चीनी फीड के विद्वान वकील श्री विकास सिंह ने 11.08.2011 को पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड *बनाम पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के रूप में 2010 के एलपीए संख्या 732 में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब और अन्य*/जसबीर सिंह *के मामले* (सुप्रा) *में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने वाली डिवीजन बेंच* ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

> "इन सिद्धांतों से, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है, चाहे वह संदर्भ का पक्ष हो या नहीं। याचिकाकर्ता सोसाइटी के सदस्य होने के नाते पीड़ित व्यक्ति हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि एक बेईमान व्यक्ति सोसाइटी का सेल्समैन हो। सेल्समैन द्वारा किए गए गबन से प्रत्येक सदस्य प्रभावित होना तय है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं और सोसाइटी के एक अन्य सदस्य द्वारा दायर आवेदन पर संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग स्वतः किया जा सकता था।

(बारह) श्री शर्मा ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब और अन्य (2) में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जहां यह माना गया है कि धारा 69 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में एक आदेश या निर्णय पारित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, कार्यवाही बीओडी की उप-समिति के एक निर्णय से समाज में ही समाप्त हो गई थी। यह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही नहीं थी और इसलिए अपर रजिस्ट्रार का यह निर्णय सही था कि पुनरीक्षण अपने आप में विचारणीय नहीं था। फैसले के पैरा 3 को उद्धृत किया जा सकता है: -

> "3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क यह है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पास पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, याचिकाकर्ता को निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से बहुत कम रोका गया था क्योंकि वह उप रजिस्ट्रार द्वारा तय किए गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसरण में जोन नंबर 3 से विधिवत चुना गया था।
>
> रजिस्ट्रार की शक्तियां। हमें इस तर्क में दम नजर आता है। अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक कार्य करने से नहीं रोका जा सकता जब तक

(2) 2001 (1) पीएलजे 81

कि ऐसे विवादों को शासित करने वाले नियमों के अनुसार उचित रूप से उठाए गए चुनाव विवाद में उसके चुनाव को रद्द नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में सतीश *मोहिंद्रू और अन्य बनाम सहायक रजिस्ट्रार,* सहकारी समितियां, गुरदासपुर और अन्य 1989 *पीएलजे 239* में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इसके अलावा, पुनरीक्षण याचिका स्वयं अधिनियम की धारा 69 के तहत सुनवाई योग्य नहीं थी। अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी निर्णय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य की जांच करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा एक याचिका पर विचार किया जा सकता है। किसी प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था जिसे रजिस्ट्रार के समक्ष चुनौती दी गई थी और न ही कोई कार्यवाही लंबित थी, जिसके औचित्य की जांच उसके द्वारा की जा सकती थी। पुनरीक्षण याचिका में जिस चीज को चुनौती दी जानी थी, वह रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चुनाव कार्यक्रम था, न कि याचिकाकर्ता के निदेशक के रूप में चुनाव का। इस मामले के मद्देनजर, रजिस्ट्रार का आदेश याचिकाकर्ता को बैंक के निर्वाचित निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, अधिकार क्षेत्र के बाहर है?

(तेरह) श्री शर्मा का तर्क है और जिसका याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा खंडन नहीं किया जा सका है, वह यह है कि प्रतिवादी पर लागू सामान्य कैडर नियम अंतिम दंड आदेश से कम है। सामान्य संवर्ग नियमावली में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो किसी व्यथित व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों अथवा राज्य सरकार के पास अपील, संशोधन अथवा समीक्षा करने में समर्थ बनाता हो। नियमों में मामले को आगे न्यायिक या अर्ध न्यायिक समीक्षा के लिए आगे ले जाने का कोई माध्यम नहीं है। 2011 के LPANo.732 में निर्णय इस तथ्य के प्रकाश में प्रदान किया गया था कि रजिस्ट्रार का नामांकित व्यक्ति निदेशक मंडल में था जिसने निर्णय लिया जो चुनौती का विषय बन गया। इसलिए, इसे अधिनियम के तहत एक निर्णय के रूप में माना जा सकता है और इसलिए, राज्य सरकार को अपील करनी चाहिए। तथ्य के इस बिंदु पर मामला अलग है। 2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 19790 में *अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव* बैंक लिमिटेड अमृतसर बनाम उप रजिस्ट्रार (ई) सहकारी समितियां, पंजाब *और एक अन्य,* इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आयोजित किया

कि गुरनाम कौर **बनाम** *स्टेट ऑफ पुन जब आदि (3***)** में भी, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा था कि अधिनियम

की धारा 69 के तहत एक संशोधन अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है।

(चौदह) मेरी सुविचारित राय में, उपरोक्त निर्णय तत्काल याचिका में शामिल विवाद को पूरी तरह से कवर करते हैं। वर्तमान मामले में भी, निलंबन आदेश और आरोप पत्र जारी करने का आदेश

अधिनियम के तहत या उसके तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया था। वे आदेश सोसायटी द्वारा सेवा नियमावली के अंतर्गत पारित किए गए थे। चैप्टर वहीं बंद खड़ा था। प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन दो निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे प्रतिवादी नंबर 2 के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, विशेष रूप से तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में। दोनों मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी यानी उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जो अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण था। वर्तमान मामले में, निलंबन आदेश और आरोप पत्र जारी करने का आदेश सोसायटी के अधिकारियों द्वारा पारित किया गया था, इसलिए, उन आदेशों के खिलाफ, अधिनियम की धारा 69 के तहत पुनरीक्षण बनाए रखने योग्य नहीं था। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित दिनांक 29.9.2008 का आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसे रद्द किया जा सकता है।

(पंद्रह) कानूनी ढांचे और इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दी गई न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के फैसले अच्छी तरह से हैं, मेरा विचार है कि न तो सुगरफेड और न ही इसके प्रबंध निदेशक निदेशक निदेशक मंडल की उप-समिति के निर्णय को चुनौती देने के लिए सक्षम थे जिसमें अधिनियम की धारा 69 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को आमंत्रित करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है खासकर जब आरसीएस का कोई नामांकित व्यक्ति मौजूद और निर्णय लेने वाला नहीं था। मुझे न्यायालय के निष्कर्ष में कोई कानूनी कमजोरी नहीं दिखती है कि धारा 69 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं था।

(सोलह) वर्तमान याचिका और संबंधित रिट याचिकाओं को तदनुसार खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।

(सत्रह)इस आदेश की एक प्रति अन्य जुड़े मामलों की फाइलों पर रखी जाए।

एस. संधू

(3) 1992 (2) पीएलआर 746

पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स 329
(घ) सहकारी समितियां
पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य *(राजीव नारायण रैना, जे।*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिअधिकारी

अंबाला, हरियाणा